

विघटन के कगार पर खड़ा पाक

पाकिस्तान आज आर्थिक और राजनीतिक विघटन की कगार पर खड़ा है। आये दिन बम विस्फोटों में दर्जनों लोगों की जान चले जाना रोजमर्रा का घटनाक्रम बन गया है। आर्थिक तौर पर पाकिस्तान की हालत जर्जर हो चुकी है। पूरी तरह अमेरिकी अनुदान की दया पर उसकी अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। शुरुआत से ही वहाँ के शासकों ने कट्टरपंथी ताकतों को हवा दी। जनवादी संस्थाओं व व्यक्तियों का निर्मम दमन किया गया। फौजी शासकों के काल में तो यह अपने चरम पर पहुँच गया। लेकिन तथाकथित लोकतांत्रिक शासन जो वस्तुतः अमेरिका की छत्रछाया से बाहर नहीं निकल पाया, के दौरान भी जनवादी संस्थाओं, छात्र संगठनों, प्रगतिशील वाम तत्वों व ट्रेड यूनियनों का भयंकर दमन हुआ।

वैसे अपने अस्तित्व में आने के बाद से पाकिस्तान लगभग 42 वर्षों तक फौजी हुकूमत के अधीन रहा। इन फौजी हुकूमरानों का निशाना जनवादी संस्थाएँ तथा ट्रेड यूनियन रहीं। तथाकथित लोकतंत्र के 28 सालों में भी ट्रेड यूनियनों व जनवादी संस्थाओं को भारी दमन झेलना पड़ा।

पाकिस्तान में महंगाई या मुद्रास्फीती की दर तेजी से बढ़ती जा रही है। बिजली, पानी व रसोई गैस की किल्लत के कारण 2200 औद्योगिक इकाइयाँ बंद हो गई हैं। सैंकड़ों हज़ार मजदूरों ने अपना रोजगार खो दिया है।

पाकिस्तान के शासकों की अमेरिकापरस्त नीति व अमेरिकी हस्तक्षेप के सामने निर्लज्ज आत्मसमर्पण ने जहाँ जनता के बीच कट्टरपंथी तत्वों का प्रभाव बढ़ा है, वहीं अमेरिकी वर्ल्ड बैंक व अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी साम्राज्यवादी संस्थाओं के निर्देश पर पाकिस्तान की सरकार लगातार जनविरोधी नीतियाँ लागू कर रही है जिससे जनता का आक्रोश दिनोंदिन बढ़ता जा रहा है।

दिनोंदिन बढ़ती आतंकवादी कार्यवाहियों व बम विस्फोटों में हताहत होने वाली ज्यादातर आम जनता होती है, हालांकि इस्लामिक कट्टरपंथियों का निशाना अमेरिकी साम्राज्यवादी संस्थान होते हैं। पाकिस्तान इस समय एक आंतरिक युद्ध एवं विग्रह की स्थिति से गुजर रहा है। पूर्ववर्ती सरकारों की तरह वर्तमान सरकार भी साम्राज्यवादियों के इशारे पर अपनी ही जनता के खिलाफ युद्ध संचालित कर रही है। उत्तर-पश्चिम प्रांत में नाटो के हमले जारी हैं तथा स्वात व बुनेर में पाकिस्तानी फौजों के हमले अपनी ही जनता के खिलाफ जारी हैं। इस अभियान में सैंकड़ों महिलायें, बच्चे और आदमी मारे गये हैं। लाखों लोग बेघरबार हो गये हैं। सभी प्रांतों में रोज-ब-रोज आत्मघाती हमले हो रहे हैं जिनमें हज़ारों लोग मारे गये हैं। 2009 में अकेले पंजाब प्रांत में ही सेना, नौ सेना पुलिस समेत 612 लोगों ने अपनी जान गंवाई है तथा 2012 लोग घायल हुए हैं।

विश्वव्यापी मंदी की मार पाकिस्तान की अर्थ व्यवस्था पर बहुत तीव्र पड़ी है। बेरोजगारी भयंकर रूप से बढ़ी है। सकल घरेलू उत्पाद जो 2006-07 में 7.8 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा था, अब वह मात्र 5.8 प्रतिशत रह गया है। महंगाई के बढ़ने की रफ्तार इस कदर तेज है कि अनाज से लेकर ईंधन तक की कीमतें विगत वर्ष नवम्बर तक 30 प्रतिशत बढ़ गई थीं। इनमें बढ़ाव जारी है। 2007-08 में विदेशी चालू खाते में घाटा बढ़ कर 16 बिलियन डालर हो चुका है।

कर्ज से लदी पाकिस्तान सरकार अपने नागरिकों पर करों का बोझ बढ़ाती गई है। करों का बोझ गरीब मेहनतकश आबादी

पर तेजी से बढ़ा है, वहीं अमीरों को करों में छूटें प्रदान की गई है। पिछले 20 वर्षों में गरीब परिवारों पर कर के बोझ में 17.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, वहीं दूसरी ओर अमीर परिवारों पर लगने वाले कर में 15.9 प्रतिशत की कमी आई है। पाकिस्तान की वित्तीय नीतियाँ अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष व विश्व बैंक द्वारा निर्देशित हैं।

पाकिस्तान में बेरोजगारी की स्थिति दिनोंदिन बदतर होती जा रही है। बेरोजगारों की संख्या प्रति वर्ष बढ़ रही है। तकरीबन दो लाख डिग्री व डिप्लोमाधारी नौजवान नौकरी की तलाश में भटक रहे हैं। कम पढ़े-लिखे अथवा निरक्षरों की बेरोजगारी की कोई आधिकारिक संख्या ही नहीं है।

आवश्यक वस्तुओं के दाम पाकिस्तान में तेजी से बढ़ रहे हैं। पानी, बिजली व गैस की सप्लाई में तीव्र कटौती की जा रही है। इन चीजों की कम आपूर्ति होने से औद्योगिक इकाइयाँ भी बड़ी संख्या में बंद हो रही हैं। विशेष तौर पर टेक्सटाइल उद्योग पर इसका असर पड़ रहा है। टेक्सटाइल उद्योगों के मालिकों के अनुसार पाकिस्तान में 75 प्रतिशत टेक्सटाइल उद्योग की इकाइयाँ बंद हो चुकी हैं और इसके चलते छः लाख श्रमिक काम से बाहर हो चुके हैं।

पाकिस्तान में कानून-व्यवस्था की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। आये दिन देश के किसी न किसी कोने में बम विस्फोट, हत्या, अपहरण की घटनाएँ होती रहती हैं। लूटमार व डकैती की घटनाएँ भी बढ़ती जा रही हैं। शासकों के लिए शासन करना दिन-ब-दिन मुश्किल होता जा रहा है और व्यवस्था का संकट दिनोंदिन गहराता चला जा रहा है। अर्थव्यवस्था का संकट एक स्थाई राजनीतिक संकट में तब्दील हो चुका है। यह संकट मौजूदा पूंजीवादी व्यवस्था में असमाधेय होता दिख रहा है। आने वाले समय में यह संकट और भी घनीभूत होगा और नये राजनीतिक संकट में अभिव्यक्त होगा। पाकिस्तान

लगातार आंतरिक विघटन की ओर भी बढ़ रहा है। खुद जहाँ शासकों ने अमेरिकी साम्राज्यवादियों के सामने निर्लज्ज आत्मसमर्पण कर के अमेरिका को अपने ही देश पर हमले व हवाई बमबारी करने का अवसर दिया है तथा अपनी संप्रभुता के हनन को स्वीकार किया है, वहीं अमेरिका के दबाव में अपनी ही जनता के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है। आतंकवाद के खिलाफ युद्ध दरअसल दक्षिण एशिया में अमेरिकी दखल को स्थायित्व प्रदान करने की नीति का ही हिस्सा है।

ऐसी स्थिति में पाकिस्तान के लोगों के भीतर अपने शासकों व अमेरिकी साम्राज्यवादियों के खिलाफ नफरत बढ़ी है। लेकिन पाकिस्तानी जनता की इस साम्राज्यवाद विरोधी भावना को स्वर देने वाला कोई प्रभावी संगठन न होने के कारण धार्मिक कट्टरपंथ को इसे भुनाने में मदद मिली है। अमेरिकी साम्राज्यवाद विरोधी तत्वों को इस्लामिक जिहादी व कट्टरपंथी तत्व अपने साथ समेट रहे हैं। लिहाजा धार्मिक कट्टरपंथी तत्वों व इस्लामिक जिहादी तत्वों की ताकत में इजाफा हुआ है। अमेरिकी साम्राज्यवाद के चाकर पाकिस्तान सरकार ने जिहादी तत्वों से निपटने के नाम पर अपनी ही जनता के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है। उत्तर-पश्चिम सीमांत प्रांत में इस्लामी जिहादियों के खिलाफ भयंकर सैनिक कार्यवाही चल रही है। इस सैन्य कार्यवाही के नाम पर लाखों की संख्या में निर्दोष जनता पर पाकिस्तान की सेना ने कहर बरपा दिया है।

पाकिस्तान के शासकों ने मौजूदा संकट का बोझ मजदूरों के सिर पर डालना शुरू कर दिया है। संकटग्रस्त अर्थव्यवस्था को उबारने के नाम पर मजदूरों को निचोड़ने-चूसने के लिए पूंजीपतियों को पूरी छूट दी जा रही है। मजदूरों के जीवन और काम की दशाएँ दिन-ब-दिन बदतर होती जा रही हैं। पाकिस्तान में केवल तीन प्रतिशत ही मजदूर संगठित क्षेत्र में हैं और ट्रेड

यूनियन के सदस्य हैं। अस्पतालों, आयुध कारखानों, सेवा क्षेत्र तथा अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में ट्रेड यूनियन के गठन की अनुमति नहीं है। मजदूरों के वेतन की स्थिति बहुत ही दयनीय है, लेकिन उन पर काम का बोझ बढ़ता जा रहा है। उन्हें चिकित्सा, सुरक्षा जैसी सुविधाएँ हासिल नहीं हैं। ठेकेदारी के तहत ज्यादा से ज्यादा मजदूरों की भर्ती की जा रही है। ट्रेड यूनियनों में शामिल होने से मजदूरों को रोका जा रहा है।

पाकिस्तान के मौजूदा पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सरकार से मजदूरों को काफी उम्मीद थी, क्योंकि इस पार्टी का जन्म मजदूर आंदोलन के दौरान 1970 के दशक में हुआ था। इसके नेता जुल्फिकार अली भट्टो अपने को समाजवादी कहते थे। पीपीपी अपने को मजदूरों का हितरक्षक घोषित करती रही है। लेकिन इस सरकार ने मजदूरों के लिए बहुत ही खतरनाक बिल पेश किया है। औद्योगिक संबंध विधेयक, 2008 नामक इस विधेयक में सरकार ने ट्रेड यूनियन बनाने व सामूहिक वार्ता के अधिकार को उनसे छीन लिया है। बाकी कानून मुशर्रफ सरकार के समय के ही हैं। मसलन आठ के बजाय 12 घंटे का कार्यदिवस, महिला मजदूरों से रात की शिफ्ट में काम कराना आदि। न्यूनतम मजदूरी 6000 रुपये (75 डालर अथवा 3375 भारतीय रुपया) घोषित की गई है, लेकिन इस पर भी कहीं अमल नहीं होता।

आसमान छूती महंगाई, आवश्यक व रोजमर्रा के इस्तेमाल के सामानों के दाम में वृद्धि, परिवहन भाड़े में बढ़ोत्तरी से मजदूरों का जीवन अत्यंत विकट होता जा रहा है। भारी संख्या में अनौपचारिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, ईंट भट्टों व पावरलूम में काम करने वाले मजदूरों को श्रम कानूनों के दायरे में रखा ही नहीं गया है। इनकी जीवन स्थितियाँ बहुत ही दयनीय हैं। इसी तरह महिलाएँ जो मूलतः लेदर, गारमेंट्स, फूड व दवा कंपनियों में हज़ारों की तादाद में कार्यरत

हैं, यूनियन बनाने के अधिकार व श्रम कानूनों कानूनों के लाभ से वंचित हैं।

पाकिस्तान को मौजूदा हालत से सिर्फ मजदूर वर्ग ही निकाल सकता है। मजदूर वर्ग का आंदोलन ही शासकों की जनविरोधी नीतियों पर अंकुश लगा सकता है तथा पूंजीवादी-साम्राज्यवादी ताकतों के चंगुल से पाकिस्तान को मुक्त कर सकता है। धार्मिक कट्टरपंथ व इस्लामी जंजुओं से भी वही निपट सकता है। पाकिस्तान के मजदूर वर्ग को कई मोर्चों पर एक साथ लड़ना होगा। पाकिस्तान का मजदूर वर्ग इस चुनौती को स्वीकार करने की ओर बढ़ भी रहा है। पाकिस्तानी शासकों की वहाँ रेलवे के निजीकरण की मुहिम तथा अन्य सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण के खिलाफ ऑल पाकिस्तान ट्रेड यूनियन फेडरेशन ने भर्तस्ना की है और इसके खिलाफ तीखा संघर्ष चलाने की घोषणा की है।

ऑल पाकिस्तान ट्रेड यूनियन फेडरेशन ने शांति के लिये और आतंकवाद के खिलाफ मुहिम चलाने का साहसिक फैसला किया है। ऑल पाकिस्तान ट्रेड यूनियन ने 2008 में शांति के लिए और आतंकवाद के खिलाफ राष्ट्रीय महासम्मेलन आयोजित किया था। इसके संगठकों का कहना है कि शांति की स्थापना के लिए उनका अभियान पूरे देश में चलाया जायेगा।

बहरहाल, पाकिस्तान के मजदूर वर्ग को पूंजीवादी एवं अमेरिकी साम्राज्यवाद परस्त शासक वर्ग के खिलाफ सामने आना होगा। धार्मिक कट्टरपंथ व अपने शासक वर्ग के अधराष्ट्रवाद को परास्त कर ही वह ऐसा कर पायेगा। ऐसा ही भारत के मजदूर वर्ग को भी करना होगा। एक दिन वह भी आयेगा जब भारत और पाकिस्तान के मजदूर-मेहनतकश देश विभाजन के कलंक को मिटा कर एशिया की धरती पर साम्राज्यवाद की कब्र खोदेंगे।

- नगेन्द्र मनराल

जल-प्रदूषण : एक भारी खतरा

जो तो हर तरह का प्रदूषण खतरनाक है। पर जल-प्रदूषण की समस्या तो विकराल है, जो अनेक रोगों को जन्म दे रही है। मनुष्य की असावधानी और उद्योगों से सिर्फ मुनाफा कमाने की बड़े उद्योगपतियों की स्वार्थपरता इस समस्या को और अधिक विकराल बना देती है। भारत में जल-प्रदूषण का सबसे प्रासंगिक उदाहरण है गंगा नदी का प्रदूषण। हिमाचल के उत्तर में गोमुख से निकली गंगा नदी अपनी हज़ारों किलोमीटर लंबी यात्रा तय करते हुए पश्चिम बंगाल को पार कर बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। इस नदी का भारत में अत्यधिक धार्मिक महत्त्व है। हमारे ग्रंथों में भी इसे प्रदूषित न करने की बातें कही गई हैं। गंगा नदी को इतना अधिक महत्त्व इसलिए दिया जाता है, क्योंकि इसके जल में पाए जाने वाले जीवाणु किसी प्रकार की गंदगी और रोगाणुओं को पनपने नहीं देते। पर इनकी भी आखिर एक सीमा है। अब तो गंगा नदी के आसपास इतने कारखाने और छोटे-बड़े कस्बे उग आए हैं कि वे अपना सारा कचरा बेपरवाह होकर गंगा में बहाए जा रहे हैं। पर वक्त आ गया है कि हम गंगा पर किए जा रहे अत्याचारों को रोकें और अपनी मानसिकता को बदलें।

सच तो यह है कि वाराणसी तक आते-आते इसका पानी इतना प्रदूषित हो चुका है कि यह कतई पीने लायक नहीं होता। यह केवल गंगा की ही नहीं, बल्कि भारत की तमाम नदियों की सच्चाई है। क्या आप सोच सकते हैं कि इन सबका नदियों की पारिस्थितिकी पर कहां तक प्रभाव पड़ता होगा?

अक्सर फैक्ट्रियों से निकलने वाले कचरे को नदियों में बहा दिया जाता है। इस कचरे में कई तरह के हानिकारक द्रव्य, ग्रीज, गहरे रंग और रसायन, सूक्ष्म जीवाणु होते हैं। कई बार धातु के बेकार टुकड़े भी होते हैं। कपड़ा मिल से निकलने वाले बेकार रेशे होते हैं या फिर चमड़ा उद्योग से निकलने वाला जानवरों का मांस, खाल इत्यादि। इसके अलावा कच्चे माल तथा मशीनों की धुलाई के लिए इस्तेमाल किया गया गरम पानी, डिटर्जेंट आदि भी होते हैं।

ये सभी चीजें बेहद क्रूरता से नदी के पानी में घोल दी जाती हैं, बगैर यह सोचे कि यह नदी पर कितना बड़ा अत्याचार है। डिटर्जेंट आदि से पैदा होने वाली झाग ऊपरी सतह को ढक लेती है, जिससे सूर्य की रोशनी नदी तक नहीं पहुंच पाती। इससे कई पौधे और मछलियाँ घुटन से मर जाती हैं। कचरे की ठोस चीजें नदी-तल तक इकट्ठी हो जाती हैं। कुछ समय बाद इनमें से हाइड्रोजन सल्फाइड जैसी भयानक गैसें

निकलने लगती हैं जो नदी के जीव-जंतुओं को बुरी तरह प्रभावित करती हैं। मछलियों और पौधों में जहरीले तत्व इकट्ठे होने लगते हैं। कभी-कभार कचरे से नदी का तापमान भी तेजी से बढ़ जाता है जिससे मछलियों का जीवन-चक्र भी प्रभावित होता है। कई बार खेतों की अत्यधिक सिंचाई से यह रसायन-मिश्रित पानी नदी या तालाब तक जा पहुंचता है। इस पानी में नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस की अत्यधिक मात्रा होती है जो नदी या तालाब के लिए हानिकारक होती है। वह इसलिए क्योंकि नाइट्रोजन आदि पोषक तत्वों की अत्यधिक मात्रा से शैवाल की ज्यादा बढ़ोत्तरी होती है। इससे पानी की ऊपरी सतह शैवाल से पूरी तरह ढक जाती है और पानी में जीव-जंतु घुटन से मर जाते हैं। इस प्रकार नदी या तालाब के जीवन का अंत हो जाता है। कई बार सीवरों का कचरा बिना परिशोधित किए ही नदी में बहा दिया जाता है। इससे कई हानिकारक धातुएं और रोगाणु नदी-जल में मिल जाते हैं और जल को प्रदूषित करते हैं। हानिकारक रोगाणुओं से मछलियों में संक्रमण फैलने का खतरा बन जाता है। खौफनाक बात यह है कि अब समुद्र भी प्रदूषण की चपेट में आ चुके हैं। समुद्रों में सबसे बड़ा खतरा तेल से होता है। समुद्र-तल से तेल निकालने के बाद बड़े-बड़े टैंकरों द्वारा दुलाई होती है। हर दस लाख टन की दुलाई में करीब एक टन तेल समुद्र में ही फैल जाता है। समुद्री जीव-जंतु जब इस तेल के संपर्क में आते हैं, तो उन्हें त्वचा के कई रोग हो जाते हैं। उन्हें सांस लेने में दिक्कत महसूस होती है। चूंकि तेल पानी से हल्का होता है, इसलिए वह स्तह पर आ जाता है। इस तरह दूर-दूर तक पानी की सतह तेल की चादर से ढक जाती है। इससे पानी में होने वाला ऑक्सीजन-संचय बंद हो जाता है। कुछ समय बाद पानी में घुली ऑक्सीजन भी खत्म हो जाती है और जीव-जंतु घुटन से मर जाते हैं। कुछ साल पहले फ्लोरिडा में एक नए तेल-उद्योग की घोषणा की गई। इससे जल-संसाधन को काफी नुकसान पहुंचाए जाने की आशंका थी। जब लोगों को यह पता चला तो उन्होंने मिलकर इसका विरोध किया। हां, विरोध का उन्होंने एक नया और नायाब तरीका खोज निकाला, जिससे इस तैलीय प्रदूषण की सच्चाई वैज्ञानिक ढंग से लोगों के सामने आई। असल में उन्होंने तेल चढ़े हुए प्लास्टिक के जीव-जंतुओं का प्रदर्शन करके अपना विरोध प्रदर्शित किया था। इससे सरकार और उद्योगपतियों की समझ में आया कि जनता अब जाग चुकी है और अपने पर्यावरण के साथ होने वाली छेड़छाड़ को अब वह जीवन-मरण का सवाल मानती है। इसमें शक नहीं कि अगर हम आज इस खतरे के प्रति जागरूक न हुए, तो कल अंधा और अंधकार भरा होगा।